The allocation of all the three types of paraffin wax to various States/Union Territories is made keeping in view the product availability. To make the product easily available, paraffin wax has been decanalised with effect from 1-4-1992.

(b) The Directorate of Industries, Haryana has requested for about 700 MTs per month of Paraffin Wax Type-III( Match Wax).

(c) Ad-hoc allocation of match wax in 1993 was made to these States to liquidate the surplus availability at that particular point of time. The demand of individual State Government is decided on merits.

**Spot purchase of Crude Oil from International Market by IOC**

5739. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the spot-purchase of crude oil from the International market for supplementing indigenous supply is canalised through the Indian Oil Corporation;

(b) if so, what is the procedure favoured by IOC for the spot-purchases in particular whether it floats a tender and awards a contract for the purchase; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Spot purchases are made through issue of tenders to parties already registered with Indian Oil Corporation and contracts awarded based on the maximum gains.

**Heavy losses to ONGC**

5740. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the Oil and Natural Gas Commission is suffering heavy losses due to taking of loans from the international capital market at higher rate of interest and investing this amount in Government securities and public deposits at lesser stte of interest;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) the remedial measures being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

**Allocation of LPG dealership to State Civil Supplies Corporation**

5741. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that State Civil Supplies Corporations have made applications for allocation of LPG dealership to them;

(b) if so, what action has been taken by the Central Government to give dealership to them;

(c) whether there is any criteria for distribution or allotment of LPG connections to the States; and

(d) what is the present State-wise allotment of LPG connections ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (b) As per current policy, Corporations owned or controlled by the State Governments, including State Civil Supplies Corporations are eligible to apply against the specific advertisements for LPG distributorships under 'Open category'. Their applications are decided on merit by the Oil Selection Boards.

(c) and (d) New LPG connections are released depending on the annual enrolment of new cutstomers, slack available with the distributors in the State, waiting lists and product availability. Allotment of new gas connections is not made on State-wise basis.

**सांसदों से प्राप्त पत्र**

5742. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांसदो द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालयों को प्रेषित किये गये पत्रों का अंतिम उत्तर नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 1-7-92 से 30 मार्च, 1994 तक की अवधि के दौरान सांसदों से कितने पत्र प्राप्त हुये और कितने पत्रों के संबंध में अंतिम उत्तर अब तक नहीं दिये गये ; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निश्चित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा)** : (क) और (ख) मंत्रालय को संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों के प्रति तीन माह की अवधि के अन्तर्गत अंतिम उत्तर भेजने के संबंध में निरन्तर प्रयास किये जाते हैं । तथापि, कतिपय संदर्भ जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करके विस्तृत जांच/छानबीन की आवश्यकता जैसे मुद्दे उठते हैं, उनको निपटाने में अधिक समय लगता है । संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों के निपटान के संबंध में आवश्यक उपचारी कार्यवाही करने हेतु मंत्रालय में विविध स्तरों पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है ।

(ग) 01 जुलाई, 1992 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के दौरान मंत्रालय को संसद सदस्यों से 4008 संदर्भ प्राप्त हुये थे । इनमें से 2385 संदर्भों के उत्तर 31 मार्च, 1993 तक दे दिये गये थे और 1623 शेष रह गये थे । 01 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994 की अवधि के दौरान मंत्रालय को शेष 1623 के अतिरिक्त 4567 संदर्भ प्राप्त हुए थे इनमें से 4784 संदर्भों के प्रति 31 मार्च, 1994 तक उत्तर दे दिये गये थे और शेष 1406 बच गये थे ।

(घ) उपर्युक्त भाग (क), (ख) और (ग) के प्रति दिये गये उत्तरों की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता ।

**गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में रसोई गैस कनेक्शनों का जारी किया जाना**

5743. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के जिलों में रसोई गैस के कितने कनैक्शन जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान गैस के और नये कनेक्शन जारी करने के लिये कोई प्रस्ताव रखे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और